

OFFICE OF THE REGISTRAR CCS HAU HISAR

RTI

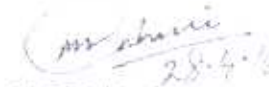
Endst.No.Admn.R.4/2016/m-614/1804-1833

Dated: 28-4-2016

In continuation to this office Endst.No.Admn.R.4/745-80 dated 18.1.2010, copy of the notification No.5/4/2008-1AR dated 18.3.2016 received from the Chief Secretary to Govt. Haryana (Administrative Reforms Department) relating to the Haryana Right to Information (Amendment) Rules, 2016 (Hindi & English) is forwarded to all Deans/Directors/Officers of the University and other COs-cum-SPIOs as well as to the Nodal Officer-cum-SPIO for Registrar's office and the 1st Appellate Authority designated by the University under RTI Act, 2005 for information and necessary action.

2. The Vice-Chancellor, CCS HAU has approved adoption of Haryana Right to Information (Amendment) Rules, 2016 in the University

3. It is requested that these instructions may be followed meticulously. All the employees may be informed accordingly. These rules may be displayed on the notice board of College/Directorate/Office so as to have access of the same by information seekers/general public/applicants


(Dr. M. S. Dahiya)
Registrar

Encl.As above

- CC: 1. COE/Advisor(Rectt.)/SPIO/ARE/ARF/ARA/ARL/Officer Incharge (Hosp), Faculty House/ CSO/P.S. to Registrar/AR(RC)-cum-DDO/Cashier.
2. Incharge, Computer Section, COBS&H, CCS HAU, Hisar.
3. Media Advisor/PRO, CCS HAU, Hisar.

HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Notification

The 18th March, 2016

No. 5/4/2008-1AR.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 7 of the Right to Information Act, 2005 (Central Act 22 of 2005), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Right to Information Rules, 2009, namely:—

1. These rules may be called the Haryana Right to Information (Amendment) Rules, 2016.
2. In the Haryana Right to Information Rules, 2009, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:—

5. Quantum of fee, Sections 6 and 7.— (1) An application for obtaining any information under Sub-section (1) of Section 6 shall be accompanied with a fee of ten rupees and shall ordinarily not contain more than five hundred words excluding annexure, address of the State Public Information Officer and that of the applicant.

Provided that no application shall be rejected only on the ground that it contains more than five hundred words.

(2) For providing information under Sub-section (1) of Section 7, the fee shall be charged from the applicant at the following rates, namely:—

- (a) two rupees for each page in A-4 or A-3 size paper, created or copied, and
- (b) if information is to be provided on a large size of paper than that of specified in clause (a), the actual cost price of such a paper shall be charged.

(3) For providing information under Sub-section (5) of Section 7, the fee shall be charged from the applicant at the following rates, namely:—

- (a) 100 rupees for providing information in a floppy,
- (b) 50 rupees for providing information in a diskette, and
- (c) if information sought is of such a nature, which is contained in a printed document of which a price has been fixed, then that information shall be provided after charging the price, fixed for that printed document. However, if only an extract or page of such a printed document is asked for, then a fee of two rupees per page shall be charged.

(4) No fee for inspection of record shall be charged, if such an inspection is made for one hour only. However, if inspection is made for a period of more than one hour, then a fee of five rupees shall be charged for every subsequent hour or fraction thereof.

D. S. DHESI,
Chief Secretary to Government, Haryana.

हरियाणा सरकार

प्रशासनिक सूचार विभाग

अभिसूचना

दिनांक 18 मार्च, 2016

सूचना 5/4/2008-1503340- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 22) की धारा 27 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा सूचना का अधिकार नियम, 2009 का आगम संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए जा सकते हैं -

1. यह नियम हरियाणा सूचना का अधिकार (संशोधन) नियम, 2009 कह जा सकते हैं।
2. हरियाणा सूचना का अधिकार नियम, 2009 के नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

5. धारा की प्रमाणां धारा 6 तथा 7.- (1) धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन कोई सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ सूचना का अधिकार की फीस लगाई जाएगी तथा सामान्य अनुसन्धान के राज्य लोक सूचना अधिकारी तथा उस अनुसन्धान के माध्यम से प्राप्त की शब्दों से अधिक नहीं होंगे।

परन्तु कोई भी आवेदन केवल इस आधार पर खर्च नहीं किया जाएगा कि इसमें पाठ की शब्दों से अधिक दिए गए हैं।

(2) धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना उपलब्ध करवाने के लिए आवेदक से निम्नलिखित दस्तों पर कौशल प्रभावित की जाएगी अर्थात् -

(क) धारा 6 में उप-धारा (1) के अधीन सूचना उपलब्ध करवाने के लिए आवेदक से निम्नलिखित दस्तों पर कौशल प्रभावित की जाएगी -

(क) यदि सूचना कापी (क) में निम्नलिखित के निम्न बड़े आकार के कागज पर प्रस्तुत कराई जाती है तो इसी कागज की कार्यालयी लम्बाई प्रभावित की जाएगी।

(ख) धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना उपलब्ध करवाने के लिए आवेदक से निम्नलिखित दस्तों पर कौशल प्रभावित की जाएगी अर्थात् -

(क) कौशल से सूचना उपलब्ध करवाने के लिए प्रस्ताव रूप।

(ख) डिजिटल में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए प्रस्ताव रूप।

(3) यदि कोई सूचना एक स्वरूप की हो, जोकि मुद्रित दस्तावेज में है, जिसकी कीमत नियत की गई है, तब यह सूचना उस मुद्रित दस्तावेज के लिए नियम कीमत प्रभावित करने के बाद उपलब्ध कराई जाएगी। तथापि यदि ऐसे मुद्रित दस्तावेज का केवल उद्धरण या पृष्ठ नंगा किया है, तब प्रति पृष्ठ की रूप की कीमत प्रभावित की जाएगी।

(4) अनिलेख के निरीक्षण के लिए कोई फीस प्रभावित नहीं की जाएगी, यदि ऐसा निरीक्षण केवल एक पृष्ठ के लिए किया गया है। तथापि यदि निरीक्षण एक पृष्ठ की अपेक्षा के लिए किया गया है, तो प्रत्येक पृष्ठावधि प्रत्येक पृष्ठ के अन्तर्गत की लिए फीस प्रभावित की जाएगी।

डी० एस० देसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।